

पी एम योजना के तहत वक्फ बोर्ड करेगा बीड में मेडिकल कॉलेज की स्थापना।

काजी समीर कि प्रशासन के साथ बैठक

बीड (संवाददाता):

बीड शहर के विकास में अब एक और गौरवशाली अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (झरनगत) योजना के तहत महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के माध्यम से बीड शहर में एक सर्वसुविधायुक्त मेडिकल कॉलेज और खेलप्रेमियों के लिए आधुनिक खेल संकुल (स्टेडियम/स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स) की स्थापना होने जा रही है।

इसी संदर्भ में आज जिलाधिकारी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी विवेक जॉनसन ने की। बैठक में महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन न. समीर काज़ी, जिला शल्यचिकित्सक डॉ. संजय



राऊत, भूमि सुधार विभाग के उपजिलाधिकारी सूर्यवंशी, एसडीएम, बीड नगर पालिका के मुख्याधिकारी, तहसीलदार बीड, जिला क्रीड़ा अधिकारी, वक्फ अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में यह निर्णय लिया

गया कि अगले १५ दिनों में इन दोनों परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी पहलुओं की जांच कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे राज्य के उपमुख्यमंत्री व बीड जिले के पालकमंत्री अजित पवार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस रिपोर्ट को मंजूरी

मिलने के बाद ही इन दोनों कामों की विधिवत शुरुआत होगी।

अधिक जानकारी के अनुसार, बीड के जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित इस अहम बैठक में यह तय किया गया कि पांगरी रोड पर खेल संकुल

और सर्वे नंबर ११५ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना

का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा।

इस संबंध में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काज़ी ने जिलाधिकारी से विस्तृत चर्चा की और इन दोनों परियोजनाओं की

आवश्यकता व उपयोगिता को लेकर विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद जिलाधिकारी ने संबंधित जिला प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे दोनों विषयों पर तकनीकी विवरणों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करें और उसे समय पर प्रस्तुत करें।

बताया गया कि इन दोनों परियोजनाओं के लिए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काज़ी के विशेष प्रयास रहे हैं। उनके प्रयासों के चलते ही यह योजना अब धरातल पर उतरने की दिशा में अग्रसर है।

जिला प्रशासन यह रिपोर्ट जल्द ही राज्य के उपमुख्यमंत्री को सौंपेगा, जिसके बाद उपमुख्यमंत्री अजित पवार स्वयं इस विषय में बैठक कर अंतिम निर्णय लेंगे।

मुंबई रेल धमाकों के सभी आरोपी बरी- हाईकोर्टने विशेष अदालत का फैसला किया रद्द

रिपोर्ट: जमीर काज़ी, मुंबई

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में १९ साल पहले हुए लोकल ट्रेनों में श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के सभी १२ आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति अनिल कोचर किलोर और एस. चांडक की खंडपीठ ने सोमवार को सबूतों, गवाहों की गवाही, और जांच में पाई गई गंभीर त्रुटियों को आधार मानते हुए यह चौकाने वाला फैसला सुनाया। इससे पहले, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मोक्का) की विशेष अदालत ने ५ आरोपियों को फांसी और ७ को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।

१२ आरोपियों में से एक की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, जबकि बाकी ११ विभिन्न जेलों में सज़ा काट रहे थे।

११ जुलाई २००६ की घटना

११ जुलाई २००६ को मात्र ११ मिनट के अंतर में पश्चिम रेलवे की

फर्स्ट क्लास बोगियों में छह स्थानों पर विस्फोट हुए थे। इन भयानक श्रृंखलाबद्ध धमाकों में २८४ लोगों की मौत हो गई थी और ७२७ यात्री घायल हुए थे। इस मामले की जांच महाराष्ट्र एंटी टेररिज़्म स्कॉड (-टड) ने की थी।

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की तैयारी सूत्रों के अनुसार, इस फैसले का गहन अध्ययन करने के बाद महाराष्ट्र सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। एटीएस की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई है कि वे इस निर्णय का विश्लेषण कर आगे की कार्यवाही तय करेंगे।

पृष्ठभूमि

३० सितंबर २०१५ को मोक्का की विशेष अदालत ने इस केस में ५ आरोपियों को मौत की सज़ा और ७ को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया था। इसके खिलाफ दोषियों ने हाईकोर्ट

में अपील की थी।

जुलाई २०२४ से बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी, जो २७ जनवरी २०२५ को पूरी हुई। सरकारी पक्ष की ओर से एएसजी राजा ठाकरे और विशेष सरकारी वकील चिमलकर ने दलीलें पेश की थीं।

हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि:

गवाहों के बयान विस्फोट के १०० दिन बाद लिए गए।

बम किस प्रकार के थे, यह जांच एजेंसी पता नहीं कर सकी।

पुलिस की जांच प्रक्रिया में कई गंभीर खामियाँ पाई गईं।

इन सभी बातों के आधार पर अदालत ने सभी १२ आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए निर्दोष घोषित कर दिया। राज्य सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देगी।

बिना रोए संघर्ष करना दिव्यांगों से सीखा जाने वाला गुण है-विधायक संदीप क्षीरसागर

बीड में दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूर्व-पंजीयन शिविर आयोजित

बीड, २१ जुलाई (प्रतिनिधि):

शारीरिक असमर्थता के बावजूद हर कदम पर संघर्ष करते हुए भी रोए बिना लगातार जूझते रहना - यह एक प्रेरणादायक गुण है, जिसे हमें दिव्यांगों से सीखकर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ऐसा विचार विधायक संदीप क्षीरसागर ने व्यक्त किया। वे बीड में आयोजित दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिक पूर्व-पंजीयन शिविर के समापन समारोह में अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे।

विधायक क्षीरसागर ने बीड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बीड शहर, बीड ग्रामीण और शिरूर कासार तालुका के शेष बचे दिव्यांग नागरिकों और वरिष्ठजनों से पूर्व-पंजीयन करवाने की अपील भी की, ताकि



वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

यह शिविर जिला परिषद के समाजकल्याण विभाग और अलिम्को संस्था के संयुक्त तत्वावधान में, सांसद बजरंग बप्पा सोनवणे की संकल्पना के अनुसार आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण वितरित करना है। उसी के

तहत इस पूर्व-जांच शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक संदीप क्षीरसागर ने की। इस अवसर पर बीड शहर और ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और उनके पूर्व-पंजीयन की प्रक्रिया संपन्न की गई।

इस अवसर पर बीड जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी

अधिकारी जतीन रहमान, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जाधव, जिला समाजकल्याण अधिकारी श्रावस्ती मेश्राम, पूर्व विधायक सैयद सलीम, राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के जिलाध्यक्ष राजेंद्र मस्के, गट विकास अधिकारी श्रीमती कांबळे तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति, दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

सांसद सुनील तटकरे और धनंजय मुंडेने शेख निज़ाम कि क़बूल कि मेज़बानी बीड शहर के लंबित मुद्दों पर सौंपा गया ज़ापन



बीड (प्रतिनिधि):

‘निर्धार नव्या पर्वाचा’ कार्यक्रम के अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सांसद सुनील तटकरे, पूर्व मंत्री व विधायक धनंजय मुंडे, महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष

रूपाली चाकणकर, विधायक विजयसिंह पंडित, प्रदेशाध्यक्ष सुरज चव्हाण, राष्ट्रीय प्रवक्ता परांजपे, कल्याण काका आखाडे, विधायक विक्रम काळे, पूर्व विधायक संजय दौंड, रमेशराव आडसकर, डॉ.योगेश

क्षीरसागर, संपादक शेख तथ्यब समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों का बीड नगर में आगमन हुआ।

इन सभी मान्यवरों के लिए शेख निज़ाम और शेख अमर के परिवार एवं मित्र मंडल की ओर से एक

स्नेहभोजन का आयोजन किया गया था।

इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे का जन्मदिन भी बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। साथ ही, बीड शहर के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों से संबंधित लंबित समस्याओं के समाधान हेतु एक ज़ापन सौंपा गया।

ज़ापन में प्रमुख रूप से निम्नलिखित माँगों की गई:

अल्पसंख्यक समाज की लड़कियों के लिए हॉस्टल (वस्तीगृह) की स्थापना

उर्दू घर की स्थापना

नया ईदगाह (बालेपीर) तक जाने हेतु कांक्र्रीट सड़क व ईदगाह परिसर का कांक्र्रीटीकरण

बिंदुसरा नदी पात्र में स्थित भूमि को ईदगाह के लिए प्रदान किया जाए (पेट बीड क्षेत्र)

पुराना बाजार वेस से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा तक सड़क निर्माण

बीड शहर के प्रमुख नालों का विकास:

सेंटर नाला (भाजी मंडई से बिंदुसरा नदी तक)

इस्लामपुरा, मोमिनपुरा, गांधी नगर,

मिह्लत नगर, मोहम्मदिया कॉलोनी, बिलावल नगर - इन सभी क्षेत्रों की सड़कें व नालियां बनवाई जाएं

कंकालेश्वर मंदिर व दरगाह परिसर का नाला और बालेपीर क्षेत्र का बांगर नाला बनाया जाए

बिंदुसरा नदी का 'नरीमन पॉइंट' की तरह विकास किया जाए जिससे उद्योग-व्यवसाय को प्रोत्साहन मिल सके

इन सभी माँगों को प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, विधायक धनंजय मुंडे और विधायक विजयसिंह पंडित के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर तटकरे साहेब ने सकारात्मक चर्चा करते हुए आश्वासन दिया कि इन मुद्दों को आदरणीय अजित पवार जी के माध्यम से हल करवाया जाएगा।

इस अवसर पर सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत शेख निज़ाम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कामगार आघाड़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष शेख अमर जैनुद्दीन, खय्यम इनामदार, सत्ता इनामदार, शेख खदोर, सैय्यद आजम, शेख जाकिर, शेख नसीर, मोमिन जुबैर, डॉ.योगेश क्षीरसागर और संपादक शेख तथ्यब अन्य अर्थीतियों ने किया।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

बीड मे पालक मंत्री खड्डों कि स्थापना।

बीड (संवाददाता): बीड शहर आज गंभीर संकटों से गुजर रहा है। खुले बिजली ट्रांसफॉर्मर, खुली नालियाँ, हर जगह गड्ढे, कचरे के ढेर, पीने के पानी की अव्यवस्था – ऐसी सैकड़ों समस्याएँ शहरवासियों के लिए किसी नरक-यातना से कम नहीं हैं। बीड के संरक्षक मंत्री अजित पवार से अपील की गई है कि जैसे बारामती महाराष्ट्र के लिए एक आदर्श है, वैसे ही बीड को भी आदर्श बनाइए। नवपर्व की थीम लेकर घूमने वालों को पहले अपनी बारामती दिखाइए – यह मांग शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) के जिलाध्यक्ष उल्हास गिराम ने की।

आज बीड शहर में छत्रपती शिवाजी महाराज चौक से लेकर राजुरी वेस तक के



रास्तों पर फैले गड्ढों के खिलाफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एक प्रमुख गड्ढे का नाम ‘पालकमंत्री गड्ढा’ रखकर उसका बाकायदा

नामकरण किया गया, और बाकी गड्ढों को ‘पालकमंत्री की लाभार्थी औलाद’ करार दिया गया। इस प्रतीकात्मक आंदोलन में गड्ढे के भीतर पालकमंत्री की तस्वीर रखी

गई, उसे गुलाल, हार चढ़ाकर और ढोल बजाकर प्रदर्शन किया गया।

उल्हास गिराम ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से लेकर राजुरी वेस

तक का मुख्य मार्ग आज गड्ढों से भरा पड़ा है। इसी मार्ग से विद्यार्थी स्कूल–कॉलेज जाते हैं, नागरिक जिला अस्पताल जाते हैं, ग्रामीण किसान अपनी सब्जियाँ बेचने इसी रास्ते से शहर में आते हैं, और व्यापारी भी इसी रास्ते पर अपना व्यवसाय करते हैं। इस मार्ग पर नगरपालिका और जिला परिषद जैसे प्रशासनिक निकाय मौजूद हैं, फिर भी हालात बदहाल हैं। उन्होंने अजित पवार से अपील की कि एक बार खुद शहर का दौरा करें, ताकि उन्हें ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा हो। साथ ही ‘नवपर्व’ की थीम लेकर घूमने वाली टीम को समझाइए और उन्हें बारामती घुमा लाइए ताकि उन्हें विकास का सही मॉडल समझ में आए। बीड की दुर्दशा

बारामती की तरह विकास में तब्दील हो, यह अपेक्षा शहरवासियों को आपसे है, इसे टूटने मत दीजिए – ऐसा भावनात्मक आवाहन भी गिराम ने किया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शिवसैनिक शामिल थे। इनमें प्रमुख रूप से: महिला संघटिका मीराताई नवले, उपजिलाध्यक्ष संजय महाद्वार, राजुभाऊ महवाले, रतन तात्या गुजर, विधानसभा प्रमुख सुशील पिंगळे, नवनाथ प्रभाळे, थिंगळे विशाल, गणेश लोणकर, विनोद गोरख, जगदीश गिराम, प्रदीप कोटुळे, सतीश सिंह परदेशी, शरद पवार, दिलीप पवार, मन्चिंद्र काळे, चंदूनाना कागदे, प्रेम ताकतोडे, बळी कोटुळे, विशाल तांबे आदि प्रमुख शिवसैनिक उपस्थित थे।

मराठवाड़ा व्यापारी परिषद में बीड जिले की सक्रिय भागीदारी

विभिन्न मुद्दों पर उठाई आवाज, मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया



बीड (प्रतिनिधि): रविवार को छत्रपति संभाजीनगर में मराठवाड़ा व्यापारी परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें बीड जिला व्यापारी महासंघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इस दौरान व्यापारियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री और संभाजीनगर के संरक्षक मंत्री संजय शिरसाठ तथा दुग्ध विकास और अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री के साथ संयुक्त बैठक आयोजित करने की मांग की गई।

दिनांक २० जुलाई को च-डखख-के श्रीमती रत्नाप्रभा बालासाहेब पवार सभागृह, चिकलठाणा एमआईडीसी, छत्रपति संभाजीनगर में इस भव्य व्यापारी परिषद का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ और दुग्ध विकास व अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे ने किया। मार्गदर्शक के रूप में मानसिंह पवार और सत्यनारायण लाहोटी उपस्थित रहे। परिषद का आयोजन अध्यक्ष आदेशपाल छाबड़ा और उनकी संचालक समिति द्वारा किया गया।

बीड जिले से भारी संख्या में व्यापारी परिषद में शामिल हुए। मराठवाड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स के २८ वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में और व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए इस परिषद का आयोजन किया गया।

इस मौके पर बीड जिला व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष श्री अशोक शेठे को आयोजकों की ओर से शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में शेठे ने बताया कि

सोलर विद्युत उत्पादन यूनिट पर सरकार नई शर्तें और बंदिशें लगा रही है, जो उद्योगपतियों के लिए बाधा बन रही हैं।

इन शर्तों को तुरंत हटाया जाए। व्यापारियों के बिजली बिल में शामिल डिमांड चार्ज और व्हीलिंग चार्ज कम किए जाएं।

बार-बार आश्वासन देने के बावजूद व्यवसाय कर (प्रोफेशनल टैक्स) अभी तक रद्द नहीं किया गया है – इसे तुरंत समाप्त किया जाए। कार्यक्रम के बाद उन्होंने यह मांगें एक ज्ञापन के रूप में मंत्रियों को सौंपा।

इस अवसर पर मराठवाड़ा व्यापारी संघ के पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण लाहोटी का भी विशेष सम्मान किया गया। उन्होंने व्यापारियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान किया।

मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि सरकार व्यापारियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करेगी और आगामी मंगलवार को व्यापारियों और मुख्यमंत्री के बीच संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा।

यह व्यापारी परिषद अत्यंत सफल रही। बीड जिले के कोने-कोने से व्यापारी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। इस दौरान उपस्थित प्रमुख व्यक्ति थे:

बीड जिला व्यापारी महासंघ के मार्गदर्शक सत्यनारायण लाहोटी, जिला कार्याध्यक्ष अशोक शेठे, शहराध्यक्ष प्रकाश कानगावकर, सुदाम चव्हाण, महासचिव तुकाराम सोळंके, लइक अहमद, झगडे साहब, बालूशेठ थिंगळे, भारत शेठे, बालाप्रसाद जाजू, गंगाभिषण करवा सहित अनेक व्यापारी बंधु और पदाधिकारी इस परिषद में शामिल रहे।

‘हनी ट्रैप’ में बीजेपीके दो समेत राज्य सरकार के ४ मंत्री शामिल: संजय राऊत का सनसनीखेज दावा

प्रफुल लोढा की जांच सीबीआयको सौंपी जाए

जमीर काज़ी की रिपोर्ट मुंबई: राज्य की राजनीति में ‘हनी ट्रैप’ के मुद्दे ने जबरदस्त हलचल मचा दी है। इस बीच शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता और सांसद संजय राऊत ने सोमवार को एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि ‘हनी ट्रैप’ का इस्तेमाल कर महा विकास आघाड़ी (चत-) की सरकार गिराई गई। राऊत ने कहा, हमारे १५-१६ विधायक और ४ युवा सांसद तोड़े गए। इस हनी ट्रैप में वर्तमान सरकार के ४ मंत्री शामिल हैं, जिनमें से २ भाजपा के हैं।

राऊत ने केंद्रीय मंत्री गिरीश महाजन और प्रफुल लोढा की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘द’ पर साझा करते हुए मांग की कि इस प्रकरण की जांच उड़ख को सौंपी जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में जनता को गुमराह किया, जबकि महाराष्ट्र में ‘हनी ट्रैप’ का बड़ा रैकेट चल रहा है।

उड़ख जांच से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।

संजय राऊत ने अपने पोस्ट में लिखा कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में कहा था कि राज्य में हनी ट्रैप जैसा कोई

मामला नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह भ्रामक जानकारी थी। उन्होंने कहा, झगड़ ने विपक्षी विधायकों को तोड़ने के लिए एऊ उड़ख के साथ-साथ हनी ट्रैप का भी इस्तेमाल किया, और इसके पीछे लोढा की भूमिका थी। अगर इन तस्वीरों की जांच उड़ख करे, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लोढा के पास पेन ड्राइव, सीडी... पुलिस दबिश में

उन्होंने दावा किया कि इस हनी ट्रैप मामले में ४ मंत्री और कई अधिकारी फंसे हुए हैं। फिलहाल पुलिस प्रफुल लोढा के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। राऊत ने कहा कि पुलिस को चार पेन ड्राइव और दो सीडी की तलाश है। इनमें जो कुछ है, वो गिरीश महाजन और देवेंद्र फडणवीस को भी मालूम है। उन्होंने यह भी कहा कि इस ट्रैप की शुरुआत दिल्ली से हुई थी, जिसका मकसद चत- सरकार को गिराना था।

राऊत ने आरोप लगाया कि इस हनी ट्रैप के ज़रिए १६-१७ विधायक और ४ सांसद बीजेपी में शामिल कराए गए। उन्हें सीडी दिखाई जाती थी और ब्लैकमेल किया जाता था। एऊ और उड़ख से यह पूरी तरह अलग मामला है। उन्होंने कहा कि लोढा

ही इस पूरे हनी ट्रैप का मास्टरमाइंड है। राऊत ने मुख्यमंत्री फडणवीस और लोढा की तस्वीर की जांच की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में आमतौर पर कोई शिकायतकर्ता नहीं होता – पीड़ित को ही ब्लैकमेल किया जाता है। अब ब्लैकमेल करने वाले खुद ब्लैकमेल हो रहे हैं।

राऊत ने बताया कि इस पूरे रैकेट की कड़ियाँ जामनेर, जलगांव, नासिक, ठाणे और दिल्ली तक फैली हैं। उन्होंने अपील की कि एकनाथ खडसे की इंटरव्यू ली जाए, जिससे कई राज उजागर होंगे। साथ ही, उन्होंने कहा कि मंगलवार के ‘सामना’ अखबार के अग्रलेख में भी कई तथ्य सामने लाए जाएंगे।

क्या है हनी ट्रैप मामला ?

इस कथित हनी ट्रैप रैकेट में ७२ से अधिक वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें ख-ड और खझड अधिकारी, तथा कुछ पूर्व और वर्तमान मंत्री शामिल हैं – ऐसा आरोप है।

इस प्रकरण की शुरुआत नासिक से हुई, जहां एक पांच सितारा होटल में कुछ संवेदनशील वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे। एक महिला द्वारा की गई शिकायत के बाद यह मामला उजागर हुआ। महिला ने बताया

कि वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं के आपत्तिजनक वीडियो उसके पास हैं।

ठाणे क्राइम ब्रांच को अब तक इस मामले में तीन शिकायतें मिली हैं और गोपनीय जांच जारी है।

एक महिला पर आरोप है कि उसने उच्च पदस्थ अधिकारियों और नेताओं को ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपये वसूलें। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने विधानसभा में एक पेन ड्राइव दिखाते हुए दावा किया कि उसमें ७२ ख-ड अधिकारियों और पूर्व मंत्रियों की क्लिप्स हैं।

मुख्यमंत्री का जवाब: सिर्फ आरोप नहीं, सबूत दो

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संजय राऊत के आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया। उन्होंने चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो राऊत सबूत दें।

फडणवीस ने कहा, जिस व्यक्ति की तस्वीर राऊत ने दिखाई, उसके फोटो हर राजनीतिक पार्टी के नेताओं के साथ हैं, जिनमें शरद पवार भी शामिल हैं। इसलिए इन आरोपों का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा, जब मैं विपक्ष में था तो सबूतों के साथ आरोप लगाता था, इसलिए कभी पीछे हटने की जरूरत नहीं पड़ी।

छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से जुना बाजार कोतवाली वेस तक की सड़क का कार्य तुरंत शुरू किया जाए,

अन्यथा १४ अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन-अमरजान पठान

बीड / प्रतिनिधि छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से राजुरी वेस, कारंजा

रोड, बलभीम चौक, जुना बाजार से कोतवाली वेस तक की सड़क का कार्य तत्काल शुरू किया जाए, अन्यथा आगामी १४ अगस्त को सुबह ११:०० बजे बीड नगर परिषद कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन शुरू किया जाएगा, ऐसी सीधी चेतावनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर अध्यक्ष अमरजान पठान ने आज दी।

पठान द्वारा दिए गए निवेदन में स्पष्ट किया गया है कि बीड शहर के मध्यवर्ती भाग से गुजरने वाली यह सड़क आम नागरिकों के लिए

अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिलहाल इसकी हालत बेहद खराब हो चुकी है। सड़क पर



जगह-जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं और बारिश के कारण वे जलमग्न हो चुके हैं। इससे न केवल यातायात में बाधा आ रही है, बल्कि किसी भी गंभीर दुर्घटना का खतरा बना हुआ है।

यह मार्ग शहर का मुख्य व्यापारी मार्ग है, जहां रोजाना

जिलेभर से व्यापारी और नागरिक आना-जाना करते हैं। सड़क की यह बदहाली अब

नागरिकों के धैर्य की परीक्षा लेने जैसी हो गई है। मनसे ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि तत्काल इस सड़क कार्य की शुरुआत नहीं की गई, तो १४ अगस्त गुरुवार को सुबह ११:०० बजे से

बीड नगर परिषद कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन किया जाएगा। यह बात बीड नगर परिषद कार्यालय, कार्यकारी अभियंता बीड, और जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपे गए निवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेखित की गई है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया

दिल्ली एजेंसी भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम अपने पद से तत्काल प्रभाव से आर्टिकल ६७(२) के तहत इस्तीफा दे दिया । उन्होंने इस्तीफे में अपने स्वास्थ्य और चिकित्सीय परामर्श का हवाला दिया है, हालांकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य का विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया ।

धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को धन्यवाद देते हुए अपने ‘शानदार कार्य संबंध’ का उल्लेख किया है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट की सराहना भी की । उन्होंने संसद में सदस्यता रखने वाले सभी सांसदों के सहयोग और सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया ।

जगदीप धनखड़ ने अपने कार्यकाल को भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की गहरी समझ और अनुभव अनुभव बताया और इसे एक विशिष्ट गौरव कहा ।

इस्तीफा कब प्रभावी हुआ ? इस्तीफा २१ जुलाई २०२५ को, स्वास्थ्य के कारण तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया गया ।

आगे क्या होगा ? उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा प्रोपोर्शनल इलेक्शन पद्धति (सिंगल ट्रांसफरैबल वोट) से किया जाएगा ।

चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की तारीख घोषित करेगा और प्रक्रिया शुरू होगी ।

इस रिक्त पद का शुभारंभिक चुनाव २०२५ में होना तय है । अगले कदम इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपे गए, इसके बाद उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हुआ ।

चुनाव आयोग चुनाव की तारीखें घोषित करेगा और चयन प्रक्रिया को गोपनीय और सही तरीके से संपन्न करेगा।

उपराष्ट्रपति पद की अचानक रिक्तता ने राष्ट्र की संवैधानिक संरचना में एक महत्वपूर्ण क्षण पैदा कर दिया है, और राजनीतिक व्यस्तता के बीच यह स्थिति संवैधानिक प्रक्रिया की परीक्षा है।